(सभी सदस्यों में प्रसारित करने हेतु)

साथियों,

20 अप्रैल 2009 को छठे वेतन आयोग को लागू करने के बारे सभी ने संगठित होकर जिस संघ-र्ा को प्रारम्भ किया था उसको आंशिक रूप से लागू करवाने में 27.8.2009 को हमें सफलता मिली। 30 जून 2010 को इस बारे अन्तिम रूप से जारी रेगुलेशन को लागू करवाने के लिए अक्टूबर 2010 में सरकार द्वारा गठित कुलपतियों के समक्ष विभिन्न संगठनों ने अपने पक्ष को रखा। लगातार प्रयासों को जारी रखते हुए 7 जनवरी 2011 को उच्चतर शिक्षा आयुक्त के कार्यालय पर घरना दिया गया। मार्च में जिला उपायुक्तों के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजे गये। पुनः 22 अप्रैल 2011 को नोटिफिकेशन जारी करवाने के बारे महानिदेशक उच्च शिक्षा के कार्यालय पर धरना दिया गया। इन सभी प्रयासों से अन्ततः 29 अप्रैल 2011 को नोटिफिकेशन तो जारी हो गया लेकिन सरकार ने अपने 27.8.09 को दिये वायदे को पूरा नहीं किया। यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन की भावना और उद्देश्य को नज़र अन्दाज करते हुए उच्च शिक्षा के विकास को राज्य में पटरी से उतारने की पूरी कोशिश की गयी है। जिसमें मुख्यतः

- अतिरिक्त वेतन वृद्धि को काट देना (एम.फिल., पी.एच.डी)
- एसोशिएट प्रौफेसर की सीधी वृद्धि को पूरी तरह मना कर देना।
- प्रोफेसर पद का कॉलेजों में न दिया जाना।
- सेवा निवृत्ति की आयु को बिना विचारे नकार देना।
- ए.पी.आई. के आंकड़े की संख्या को बिना आधार के बढ़ा देना।
- प्राचार्य के भत्ते को न स्वीकार करना।
- कॉलेज में उपस्थिति 9 से 4.30 तक अनिवार्य करना।
- अध्यापन समय ;वता स्वंकद्ध में भी अनावश्यक बढ़ोतरी करना।
- साथ ही समय-समय पर सरकार द्वारा पारित आदेश इस नोटिफिकेशन पर भी प्रभावी होंगे।

इसी प्रकार के अनुचित और अतार्कित निराधार आदेशों का नोटिस लेते हुए एच.सी.टी.ए. एचफुक्टों के बैनर के नीचे संघर्ा करने के लिए बाध्य है। यदि संघर्ा के द्वारा समय रहते सरकार व उसके नीति निर्धारकों के मनमाने रवैये पर अंकुश नहीं लगाया गया तो उच्च शिक्षा की स्थिति तथा हम सभी अध्यापकों की दशा भवि-य में निश्चय ही अंधकार पूर्ण हो जायेगी। इसके लिए जरूरी है हम सब मिलकर पुराने जोश-खरोश के साथ अपने जायज अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द करें। एच.सी.टी.ए. ने इसके लिए एचफुक्टो के नेतृत्व में उसके द्वारा दिखाये संघर्ा के मार्ग पर पूरी ताकत और संगठन के साथ चलने का निर्णय लिया है। संघर्ा के इस चरण मे सबसे पहले एचफुक्टो के द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उनको हम सभी ने पूरे तन-मन से सफल बनाना है।

8 मई 2011 को एच.सी.टी.ए. की बैठक में 'एचफुक्टों' के निर्देशित तीन सूत्रों को सर्व-सम्मति से पारित किया तथा सभी सदस्यों को इसमें सक्रिय भागदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया।

1- 8 मई 2011 को विभिन्न संगठनों के सदस्यों का एक बड़ा प्रतिनिधि मण्डल मुखमन्त्री के रोहतक कैम्प आफिस पर प्रदर्शन कर अपना मांग पत्र (ज्ञापन) सौंपेगा। इसमें सभी कार्यकारिणी के सदस्य अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे।

2- 9 मई 2011 को मांग-पत्र प्रत्येक यूनिट के अध्यक्ष एवम् सचिव के द्वारा मुख्य मन्त्री को तार (टेलीग्राम) के द्वारा भेजा जाये साथ ही सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवा कर मुख्यमंन्त्री के नाम स्पीड-पोस्ट भी किया जाये। मांग-पत्र का ड्राफ्ट सभी यूनिट एसोसियेसन की वेब साईट ीबजंण्पद से डाउन लोड कर सकती है।

3- 11 मई 2011 तक यदि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के कार्य का पूर्ण रूप से बहि-कार किया जायेगा। सभी यूनिट के पदाधिकारी अपने यहां चल रहे मूल्यांकन केन्द्र पर इसको सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन का कार्य न हो।

इसके बाद संघर्ा की रणनीति पर विचार करते हुए एचफुक्टो जो निर्णय लेगी उससे आपको निरन्तर अवगत करवा दिया जायेगा तथा उसे हमें पूरी तरह साकार और सार्थक करना है।

अध्यापक एकता जिन्दाबाद!

(डॉ0 नरेन्द्र सिंह)

महासचिव